



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 5 अप्रैल, 2006/15 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 5 अप्रैल, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-अधिक मांगे/1-22/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2006 को हिमाचल प्रदेश

विधान सभा में पुरस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनाएँ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित /—
(जे० आर० गाज़टा),
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियाँ, जिनका योग 20,59,55,29,893 (बीस अरब, उनसठ करोड़, पचपन लाख, उन्नतीस हजार आठ सौ तरयानवें रुपये) हैं, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभावों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 20,59,55,29,893 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियाँ, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी। विनियोग।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा एवं निर्वाचन (राजस्व)	—	1,50,470	1,50,470
4	सामान्य प्रशासन (पूँजी)	11,27,12,037	—	11,27,12,037
5	भू-राजस्व (राजस्व)	1,89,67,644	—	1,89,67,644
8	शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति (राजस्व)	53,45,46,668	—	53,45,46,668
	(पूँजी)	66,39,734	—	66,39,734
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व)	16,81,241	—	16,81,241
	(पूँजी)	1,953	—	1,953
10	लोक निर्माण (राजस्व)	81,30,35,762	—	81,30,35,762
12	सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	1,79,50,810	—	1,79,50,810
	(पूँजी)	24,17,428	—	24,17,428
13	भू एवं जल संरक्षण (पूँजी)	89,96,330	—	89,96,330
14	पशुपालन एवं डेरी विकास (पूँजी)	4,32,183	—	4,32,183
15	मत्स्य (पूँजी)	6,41,552	—	6,41,552
17	सड़कों व पुल (राजस्व)	4,96,23,772	—	4,96,23,772
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	33,87,36,372	—	33,87,36,372
23	जल एवं विद्युत विकास (राजस्व)	22,81,06,376	—	22,81,06,376
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण (राजस्व)	1,23,47,727	—	1,23,47,727

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास । (राजस्व)	32,18,03,395	—	32,18,03,395
29	वित्त (राजस्व)	8,85,69,666	—	8,85,69,666
	(पूँजी)	—	17,80,40,81,084	17,80,40,81,084
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	19,47,96,612	—	19,47,96,612
	(पूँजी)	3,92,91,077	—	3,92,91,077
	जोड़ (राजस्व)	2,62,01,66,045	1,50,470	2,62,03,16,515
	(पूँजी)	17,11,32,294	17,80,40,81,084	17,97,52,13,378
	कुल जोड़	2,79,12,98,339	17,80,42,31,554	20,59,55,29,893

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख 5 अप्रैल, 2006

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन. ए.ए. (4) 1/2001-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख 5 अप्रैल, 2006.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2000-2001 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2006.

Authorisation of a further sums of Rs. 20,59,55,29,893 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2000-2001.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 20,59,55,29,893 (Twenty hundred fifty nine crore, fifty five lakhs, twenty nine thousand eight hundred ninety three rupees) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2000-2001 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2000-2001.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Number of Demand	2 Services and purposes		3		
			Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consoli- dated Fund	Total
			Rs. —	Rs. 1,50,470	Rs. 1,50,470
1	Vidhan Sabha and Election.	(Revenue)	—	1,50,470	1,50,470
4	General Administration	(Capital)	11,27,12,037	—	11,27,12,037
5	Land Revenue	(Revenue)	1,89,67,644	—	1,89,67,644
8	Education, Sports, Art and Culture.	(Revenue)	53,45,46,668	—	53,45,46,668
9	Health and Family Welfare.	(Revenue) (Capital)	16,81,241 1,953	— —	16,81,241 1,953
10	Public Works	(Revenue)	81,30,35,762	—	81,30,35,762
12	Irrigation and Flood Control.	(Revenue) (Capital)	1,79,50,810 24,17,428	— —	1,79,50,810 24,17,428
13	Soil and Water Conservations.	(Capital)	89,96,330	—	89,96,330
14	Animal Husbandry and Dairy Development.	(Capital)	4,32,183	—	4,32,183
15	Fisheries	(Capital)	6,41,552	—	6,41,552
17	Roads and Bridges	(Revenue)	4,96,23,772	—	4,96,23,772
20	Rural Development	(Revenue)	33,87,36,372	—	33,87,36,372

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
23	Water and Power Development. (Revenue)	22,81,06,376	—	22,81,06,376
24	Stationery and Printing (Revenue)	1,23,47,727	—	1,23,47,727
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development. (Revenue)	32,18,03,395	—	32,18,03,395
29	Finance (Revenue)	8,85,69,666	—	8,85,69,666
	(Capital)	—	17,80,40,81,084	17,80,40,81,084
31	Tribal Development (Revenue)	19,47,96,612	—	19,47,96,612
	(Capital)	3,92,91,077	—	3,92,91,077
	Total (Revenue)	2,62,01,66,045	1,50,470	2,62,03,16,515
	(Capital)	17,11,32,294	17,80,40,81,084	17,97,52,13,378
	Grand Total	2,79,12,98,339	17,80,42,31,554	20,59,55,29,893

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2000-2001.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the 5th April, 2006.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-A (4)-1/2001-II]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject-matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2006, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2006

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2000-2001 in excess of the amount authorized or granted for those services for that year.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :
the 5th April, 2006.